

असाधारस्य Extraordinary

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii) प्रापिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

चं. 559] नई विस्ती, बृहस्पतिवार, सितन्बर 27, 1990/अपरिवन 5, 1912 No. 559] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 1990/ASVINA 5, 1912

इस भाग में भिन्न पूछ कंक्या की काती है विकसे कि यह अलग संकलन के कप में रक्षा का सक्षे

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1990

का.भा. 747 (भ) :—राष्ट्रपति सविधान के भनुक्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-भावंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, धर्षात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-माबंटन) (वो सौ सेरहवां संगोधन) नियम, 1990 है।

- (2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।
- 2. भारत सरकार (कार्य-ग्राबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय प्रनुसूची में,--
- (i) "कृषि मंत्रालय" शोर्षेक के प्रधीन "ग. ग्रामीण विकास विभाग" उपशीर्षक के नीचे,—
- (क) प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नलिखिन प्रविष्टि रखी जाएगी ग्रंथींस् :—

 "8. प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्थास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण और
 पोषाहार कार्यक्रमों के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम ग्रावश्यकता कार्यक्रम
 से संबंधित सभी मामलों का नोडीय उत्तरदायित्व ।
- (ख) प्रविष्टि 15 के स्थान पर निम्निलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, श्रर्थात् :--धार्मा प्राप्ताम जिसके अंतर्गत ग्रामीण ग्रावास नीति भी है और देश में
 उससे संबद्ध और ग्रानुषंगिक सभी मामले ग्रथवा ग्रामीण योजना, जहां तक वह
 ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हो।",
- (ii) "शहरी विकास मंत्रालय" शीर्षक के भ्राधीन प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, श्रायंतु :—

"12. मावास नीति और कार्यंक्रम का तैयार किया जाना (म्रामीण म्रावास को छो इकर, जिससे मानीण विकास विभाग को सौंपा गया है) योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, भावास, निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक संबंधी श्रांकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत हटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय श्रावास नीति का नोडीय उत्तरदायित्य।

रामस्वामी वेंकटरामन, राष्ट्रपति

[फा.सं. 74/2/1/90-मंत्रि.] दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1990

S.O. 747(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article of the Constitution, the President hereby makes the following rules further

to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:---

- 1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and thirteenth Amendment) Rules, 1990.
 - (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—
- (i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMEEN VIKAS VIBHAG)",—
 - (a) for entry 8, the following entry shall be substituted, namely:
 - "8. Nodal responsibility for all matters relating to the Minimum Needs Programme in rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification and the nutrition programmes.";
 - (b) for entry 15, the following entry shall be substituted, namely:
 - "15. Rural housing including Rural Housing Policy and all matters germane and incidental thereto under country or rural planning, in so far as it relates to rural areas.";
 - (ii) under the heading "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)", for entry 12, the following entry shall be substituted, namely:—
 - "12. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development), review of the implementation of the Plan schemes, collection' and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures for reduction of building costs and nodal responsibility for National Housing Policy."

R. VENKATARAMAN, PRESIDENT

[No. 74|2|1|90-Cab.]
D. DAS GUPTA, Jt. Secy.

•		